

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 644]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2010—पौष 7, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

क्र. एफ.-ए-3-34-2010-1-पांच (103).—यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन व्यापारियों की करनिर्धारण व पुनः करनिर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन कैलेण्डर वर्ष 2010 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को गुण-दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु करनिर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये विहित समय-सीमा और आगे बढ़ाई जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियमों के अधीन प्रत्येक व्यापारी के सम्बन्ध में, करनिर्धारण और पुनः करनिर्धारण की ऐसी प्रत्येक कार्यवाही को पूर्ण करने की कालावधि, जो 31 दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण नहीं की जा सकी है, 30 अप्रैल, 2011 तक बढ़ाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव,  
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

क्र. ए-3-34-2010-1-पांच, (103).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-34-2010-1-पांच, (103), दिनांक 28 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव,

Bhopal, the 28th December, 2010

F -No. A-3-34-2010-1-V-(103).—WHEREAS, the State Government is satisfied that all such assessment and reassessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2010 under the provisions of sub-section (7) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) can not be completed within the prescribed period, despite all possible efforts being made by the assessing authorities, and that in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings be extended further.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, extends upto 30th April, 2011, the period for completion of every such assessment and reassessment proceeding in respect of every dealer, under the said Acts, which is not completed by the 31st December, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.